शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 49 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 49 अंक – 17 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 15 – 22 अप्रैल 2024 मूल्य पांच रूपये

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा द्वारा उठाये सवालों पर खामोश क्यों है?

शिमला/शैल। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर लगातार हर मंच से यह दावा कर रहे हैं कि इन चुनावों के बाद सुक्खू सरकार गिर जायेगी और भाजपा की सरकार बन जायेगी।

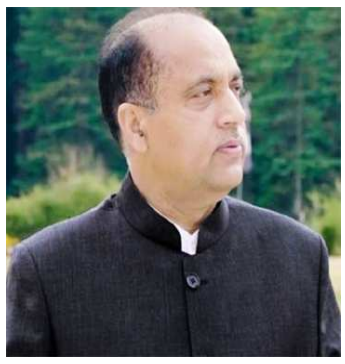

यह सब किस गणित से संभव होगा इसका खुलासा नहीं किया जा रहा है। क्योंकि वर्तमान में यदि भाजपा छः के छः उपचुनाव भी जीत जाये तो भी उनकी संख्या 31 ही होती है और इससे वह बहुमत में नहीं आते। इसलिये जयराम का सरकार गिरने का दावा एक पहेली बनकर रह जाता है। संभव है कि भाजपा किसी और योजना पर भी काम कर रही हो जयराम के इन दावों का इतना असर अवश्य हुआ है कि भाजपा के जिन विधायकों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के तहत निष्कासन तक की स्थिति पहुंच गई थी उस अध्याय पर फिलहाल विराम लग गया है। सुक्खू सरकार विधानसभा पटल पर बजट पारण के दौरान ही गिर जाती यदि भाजपा के पन्द्रह विधायकों को सस्पेंड न कर दिया जाता। सुक्खू सरकार को सदन में गिरने से बचने का श्रेय नेता प्रतिपक्ष जयराम को ही दिया जा रहा है। लेकिन जयराम इस विषय पर खामोश हैं।

इस चुनाव के मुद्दे क्या होंगे? क्या उन मुद्दों पर जन बहस हो पायेगी? क्या कांग्रेस के बागियों द्वारा उठाये गये सवाल आधारहीन है? ऐसे बहुत से मुद्दों पर जन बहस का वातावरण क्यों नहीं बन पा रहा है? कांग्रेस की सरकार ने आते ही भाजपा पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाया था। इस आरोप को प्रमाणित करने के लिए सरकार श्वेत पत्र लेकर भी आयी। श्वेत पत्र का जवाब देने के लिए भाजपा अध्यक्ष डॉ. बिंदल आरटीआई के माध्यम से सुक्खू सरकार द्वारा लिये गये कर्ज की जानकारी लेकर आये। यह सामने आ गया कि इस सरकार ने चौदह माह में चौदह हजार करोड़ का कर्ज ले लिया है। यह कर्ज कहां खर्च हुआ इस पर चुनाव के दौरान खंलासे और जवाब सामने आने चाहिए थे। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। यहां तक की भाजपा में शामिल हुये कांग्रेस के बागियों द्वारा उठाये गये सवालों को भी भाजपा नेतृत्व आगे नहीं बढ़ा रहा है। क्या नेता प्रतिपक्ष बागियों द्वारा पूछे जा रहे सवालों से सहमत नहीं है?

सरकार द्वारा प्रतिमाह औसतन एक हजार करोड़ का कर्ज लेना एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि इसका भार प्रदेश के हर आदमी पर पढ़

रहा है। आम आदमी को यह जानने का हक है कि यह पैसा खर्च कहां हो रहा है। राजेन्द्र राणा ने शिमला को 24 घंटे पानी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विश्व बैंक द्वारा 460 करोड़ की स्वीकृत डीपीआर का ठेका 860 करोड़ में कैसे पहुंच गया? शिमला की जनता पर इतना कर्ज बोझ क्यों डाल दिया गया? सुधीर शर्मा ने बिजली की खरीद बेच का काम बिजली बोर्ड के बजाये निदेशक बिजली के माध्यम से एक प्राइवेट आदमी को क्यों दे दिया। इसका प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर कितना प्रभाव पड़ेगा? सुधीर शर्मा ने यह भी खुलासा सामने रखा कि इस सरकार ने सत्ता संभालते ही विभागों के पास पड़े पैसे को सरकार में वापस मांग लिया। इस कारण से विभागों में देनदारियां खड़ी हो गयी। बागियों द्वारा उठाये गये यह सवाल न केवल गंभीर हैं बल्कि प्रदेश पर दूरगामी प्रभाव डालने वाले हैं। आज चुनाव के समय में इन सवालों को सार्वजनिक बहस का मुद्दा बनाना नेता प्रतिपक्ष और पूरी भाजपा का है। लेकिन इन सवालों को भाजपा नेतृत्व द्वारा आगे न बढ़ाया जाना कई तरह की नई आशंकाओं को जन्म दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस चुनाव को विधायकों के बिकने, दोषीयो को जेल की सलाखों में डालने, बिकाऊओं को हराने और

सरकार गिराने के जुमलों तक ही बांधकर रखने की योजना पर काम हो रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि कांगड़ा और हमीरपुर के टिकट आबंटन कांग्रेस द्वारा की जा रही देरी भी एक बड़ी योजना का हिस्सा है।

क्या बाली का पत्र परोक्ष में बागियों के मुद्दों को समर्थन दे गया?

पहले स्व. जी.एस.बाली और अब आर.एस.बाली द्वारा रोजगार यात्राएं निकालने से प्रमाणित हो जाता है कि बेरोजगारी प्रदेश का बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी की ही बात राजेंद्र राणा और दूसरे बागी कर रहे थे।

शिमला/शैल। कांग्रेस अभी तक कांगड़ा और हमीरपुर के लोकसभा क्षेत्र तथा छः विधानसभा उपचुनावों के लिये उम्मीदवारों का चयन नहीं कर पायी है। कांगड़ा से नगरोटा – बगवां के विधायक आर. एस.बाली का नाम भी संभावितों के रूप में मीडिया चर्चा में आया और इसी चर्चा को आधार बनाकर बाली ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम एक पत्र लिख दिया। यह पत्र भी मीडिया में चर्चा में आ गया। बाली ने इस पत्र में पार्टी के लिये उनके योगदान का उल्लेख करते हुये अपने स्व. पिता श्री जी.एस. बाली द्वारा 2012 में बेरोजगार यात्रा शुरू करने का जिक्र उठाया है। दावा किया है कि इसी रोजगार यात्रा से कांग्रेस की प्रदेश में सत्ता में वापसी हुई। इसी रोजगार यात्रा को उन्होंने भी शुरू किया दो माह में लम्बी यात्रा करने के बाद नगरोटा – बगवां में एक विशाल चुनावी रैली में इसका समापन हुआ। बाली ने दावा किया है कि जिन – जिन क्षेत्रों से होकर यह यात्रा गुजरी है वहां पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। बाली बेरोजगारी को प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा मानते हैं। बाली के मुताबिक इसीलिए सुक्खू सरकार ने पांच लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। बाली ने अन्य विकास कार्यो के साथ अपने चुनाव क्षेत्र में पांच हजार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने

शेष पृष्ठ 2 पर.....

राज्यपाल ने परवाणु में जल जनित रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी उपायों की समीक्षा की

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने सोलन जिला के परवाणु स्थित परिधि गृह में जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में परवाणु क्षेत्र में सामने आये डायरिया के मामलों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिये किये गए उपायों की समीक्षा की गई।

राज्यपाल ने कहा गर्मियों के मौसम में जल जनित रोगों के फैलने का अंदेशा बढ़ जाता है। ऐसे में पेयजल स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने परवाणु क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों में डायरिया के मामले सामने आने पर संबंधित विभागों से अब तक उठाये गये कदमों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि पेयजल के प्रदूषित होने के कारणों का शीघ्र पता लगाने और इसके लिए एक संयुक्त टीम गठित करने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने अभी तक सभी विभागों के साथ मिलकर पूरी तत्परता से कार्य किया है।

शिव प्रताप शुक्ल ने डायरिया से पीड़ित रोगियों के उपचार के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने रोगियों के उपचार एवं डायरिया की रोकथाम के लिए उठाये गये कदमों पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि लोगों में जलजनित रोगों की रोकथाम के लिए बरती जाने वाली सावधानियों का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने लोगों का भी आहवान किया कि वे नियमित तौर पर पेयजल भंडारण टैंकों की साफ-सफाई करें और इसमें निश्चित मात्रा में क्लोरीन इत्यादि डालें तथा पानी को उबालकर ही उपयोग में लाएं।

उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने परवाणु क्षेत्र में डायरिया व अन्य जल जनित रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए चलाये जा रहे सघन अभियान की विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में मामले सामने आने पर तत्काल सहायक आयुक्त (प्रोटोकॉल) की अध्यक्षता में बैठक कर एक कार्य बल (टास्क फोर्स) गठित किया गया है। इसमें स्वास्थ्य विभाग, हिमुडा, नगर परिषद, जल शक्ति सहित संबंधित विभागों को शामिल किया गया है। यह कार्य बल निरंतर ऐसे मामलों की निगरानी भी कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के पेयजल स्रोतों एवं ट्रीटमेंट प्लांट से पेयजल के नमूने एकत्र कर जांच के लिए भेजे गये हैं। पेयजल आपूर्ति में लगे टैंकरों की भी जांच की जा रही है।

उपायुक्त ने कहा कि पेयजल के प्रदूषित होने के कारणों की जांच के लिए परवाणु नगर परिषद के सभी नौ वार्डो में तत्काल अभियान शुरू किया जाएगा। इसमें नगर परिषद, हिमुडा, लोक निर्माण विभाग सहित स्वास्थ्य विभाग से भी कर्मी शामिल किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि डायरिया के मामलों में अब कमी दर्ज की गई है।

स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर जाकर दैनिक आधार पर जांच कर रही हैं। जल भंडारण टैंकों व ड्रम इत्यादि की जांच करने के साथ ही इनकी साफ-सफाई के लिए क्लोरीन की गोलियां वितरित की गई हैं। डायरिया प्रभावित लोगों को ओआरएस के पैकेट भी वितरित किए गए हैं। अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचे रोगियों में से अधिकांश ठीक होकर घर भेजे जा चुके हैं। खंड चिकित्सा अधिकारी धर्मपुर को पेयजल के सैंपल एकत्रित करने तथा नियमित तौर पर निगरानी एवं जांच के निर्देश दिए गए हैं। हिमुडा के माध्यम से भी पानी के नमूने एकत्र किए गए हैं और पेयजल स्रोतों की साफ-सफाई व क्लोरीनेशन की गई है। स्वास्थ्य विभाग की आशा कार्यकर्ताओं, नगर परिषद, टकसाल व जंगेशु पंचायतों के सचिवों, विभिन्न क्लबों व स्थानीय संगठनों के माध्यम से भी जलजनित रोगों की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया है।

दुर्गाष्टमी के अवसर पर राजभवन में फलाहार ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने प्रदेशवासियों को दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं दी और राज्य की सुख-समृद्धि की प्रार्थना की। अपने शुभ कामना संदेश में उन्होंने कहा कि यह त्यौहार हम सभी को सत्य के पथ पर चलने और बुराइयों पर विजय प्राप्त करने का संदेश देता है।

इस पावन अवसर पर राजभवन में फलाहार ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इससे पहले, राज्यपाल और लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल ने शिमला के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल काली बाड़ी मंदिर में पूजा-अर्चना की और भक्तों को प्रसाद भी वितरित किया।

राम नवमी पर राज्यपाल ने जाखू मंदिर में पूजा-अर्चना की

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अवतरण दिवस, राम नवमी की देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

राम नवमी के पावन अवसर पर राज्यपाल ने शिमला के प्रमुख धार्मिक स्थल जाखू मंदिर जाकर पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल भी उनके साथ थीं। राज्यपाल ने कहा कि यह शुभ दिन लोगों के जीवन में सुख, शांति, और समृद्धि का प्रतीक बने। उन्होंने सभी से भगवान राम के आदर्शो को अपनाने का आहवान किया।

आवश्यक सेवाओं में तैनात व्यक्तियों को प्राप्त होगी डाक मतपत्र सुविधा: मुख्य निर्वाचन अधिकारी

शिमला/शैल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने आवश्यक सेवाओं की श्रेणी के विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आगामी लोकसभा और विधानसभा उप-चुनावों के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वर्गीकृत आवश्यक सेवाओं में तैनात व्यक्ति अनुपस्थित मतदाताओं के रूप में पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने के लिए पात्र होंगे। इस सुविधा के लिए आवश्यक सेवाओं में तैनात व्यक्तियों को नोडल अधिकारियों द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक होगा कि मतदान के दिन वे ड्यूटी पर तैनात हैं। इस सुविधा के लिए उन्हें संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी को 12 मई, 2024 तक फार्म 12डी जमा करवाना होगा।

उन्होंने कहा कि इस श्रेणियों में चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ और एम्बुलेंस सेवाएं, अग्निशमन विभाग के आवश्यक ड्यूटी कर्मचारी, लम्बे रूटों पर तैनात चालक और परिचालक, दुग्ध प्रसंघ और सहकारी समितियों के दूध आपूर्ति सेवा में तैनात कर्मचारी, मीडियाकर्मी, पंप ऑपरेटर और टर्नर, इलेक्ट्रीशियन और लाइन-मैन के अलावा आवश्यक सेवा पर तैनात जेल कर्मचारी भी शामिल हैं जिन्हें पहली मर्तबा आवश्यक सेवाओं के तहत लाया गया है।

इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि इन श्रेणियों के अधिकारियों व कर्मचारियों को फार्म 12-डी भरना होगा और नोडल अधिकारी फार्म के भाग-2 में अपना प्रमाण पत्र भी देंगे। नोडल अधिकारी इसे संबंधित रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी को प्रेषित करेंगे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि अनुपस्थित मतदाताओं को फार्म पर हस्ताक्षर और मोबाइल नम्बर लिखना अनिवार्य होगा जिसे पोस्टल बैलेट सेंटर पर तैनात राजपत्रित अधिकारी सत्यापित करेंगे। पोस्टल बैलेट सेंटर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में निर्धारित तीन दिन तक खोले जाएंगे।

पोस्टल बैलेट सेंटर के अलावा इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूर्ण करने के लिए विशेष सहायक रिटर्निंग आफिसर को नामित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आवश्यक सेवाओं में तैनात सभी व्यक्ति, जिन्होंने डाक मतपत्र श्रेणी के लिए आवेदन किया है, उन्हें पीवीसी स्थल के पूरे पते, तिथि और समय के बारे में एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि जब मतदाता का पीवीसी में मतदान करने के लिए आवेदन स्वीकृत हो जाता है और किसी कारणवश वह पीवीसी में मतदान के लिए उपस्थित नहीं हो पाता है ऐसी स्थिति में उसे डाक मतपत्र भी नहीं भेजे जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि अनुपस्थित मतदाता आवेदन स्वीकृत होने के बाद पीवीसी के अलावा और कहीं पर भी मतदान नहीं कर सकते।

उन्होंने कहा कि जिन विभागों ने राज्य नोडल अधिकारी और जिला नोडल अधिकारी नियुक्त नहीं किए हैं, वे शीघ्र उनकी नियुक्ति सुनिश्चित कर निर्वाचन विभाग को सूचित करें।

उन्होंने कहा कि विगत विधानसभा चुनाव-2022 में आवश्यक सेवाओं में तैनात व्यक्तियों के लिए 1181 पोस्टल बैलेट जारी किए गए थे, जिसमें से 872 पोस्टल बैलेट प्राप्त हुए।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी दलीप नेगी, संबंधित विभागों के अधिकारी और राज्य नोडल अधिकारी उपस्थित रहे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

चैत्र नवरात्रों में 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आये शक्तिपीठों में

शिमला/शैल। प्रदेश में चैत्र नवरात्रों के दौरान विभिन्न शक्तिपीठों में प्रदेश व पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत अन्य राज्यों से करीब 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लंम्बी कतारों में लग कर अपना शीश नवाया।

हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा इन शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, कानून एवं व्यवस्था व यातायात व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रबन्ध किए थे। सभी शक्तिपीठों में जिला पुलिस के साथ भारतीय आरक्षित वाहिनियों से पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात किया था।

जहां हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रदेश में होने वाले लोकसभा, राज्य विधानसभा के उप चुनावों व अन्य राज्यो में होने वाले चुनावों को शांतिपूर्वक करवाने के लिए दिन-रात कार्य कर रही है वहीं प्रदेश पुलिस ने इन मेलों के दौरान बेहद पेशेवर तरीके से कार्य किया जिस कारण शक्तिपीठों में भारी मात्रा में आये श्रद्धालुओं ने निडर होकर अपना शीश नवाया।

मेलों के दौरान कोई भी सड़क दुर्घटना, अन्य दुर्घटना व श्रद्धालुओं को कोई भी जान-माल की हानि नहीं हुई।

हिमाचल प्रदेश पुलिस, आम जनता की पेशेवर तरीके से सुरक्षा, अपराध को नियंत्रण करने व किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने हेतु निरंतर कार्यरत व सदैव तत्पर है।

शक्तिपीठों में आये श्रद्धालुओं व वाहनों का ब्यौरा

Piligrim Data during Chaitra Navratras

Distt	Name of temple	No. of Piligrims visited	HMV	LMV	Two wheelers
Una	Chintpurni	333100	404	2531	14775
BPR	Sri Naina Devi Ji	198355	880	22064	13449
Kangra	Jawalji	122400	673	4110	6325
	Brejeshwari Temple	51680	565	1049	1721
	Chamunda Devi	88000	660	5310	6890
Sirmaur	Mata Bala Sundri Temple	490000	2190	13298	17966
Total		1283535	5372	48362	61126

राज्य सरकार के प्रयासों से शिंकुला टनल को मिली एफसीए क्लीयरेंस:सीएम

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार के प्रयासों से

शिंकुला टनल बनने का रास्ता साफ़ हो गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने लाहौल और लद्दाख को जोड़ने के लिए 4.1 किमी सुरंग बनाने को एफसीए क्लीयरेंस प्रदान कर दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस महत्वपूर्ण सुरंग के निर्माण को राज्य सरकार ने प्राथमिकता दी और विशेष अधिकारी नियुक्त कर केंद्र सरकार से स्वीकृती प्रदान करवाई। राज्य सरकार के प्रयासों से ही टनल निर्माण के लिए एफसीए क्लीयरेंस प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि सुरंग के साथ-साथ यहां एक हैलीपैड और कार्यालय परिसर का निर्माण भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि टनल के साउथ पोर्टल के साथ-साथ लगभग 3800 मीटर हिस्सा हिमाचल प्रदेश में बनेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सुरंग के निर्माण से लद्दाख तक सभी मौसम में जाना संभव हो पाएगा और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख तक पहुँचने का यह सबसे छोटा रास्ता होगा। इससे बर्फ़बारी के बीच भी गाड़ियों की आवाजाही हो पाएगी। उन्होंने कहा कि शिंकुला टनल का निर्माण सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा तथा सुरक्षा बलों की आवाजाही सुगम बनेगी। यह टनल समुद्र तल से 4800 मीटर पर शिंकुला दर्रे के नीचे बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि टनल के निर्माण से लाहौल क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बल मिलेगा जिससे क्षेत्र में भी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और क्षेत्रवासियों के जीवनस्तर में सुधार आएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में टनल के निर्माण को प्राथमिकता दे रही है, ताकि राज्य के निवासियों के साथ-साथ पर्यटकों को बेहतर सुविधाएँ प्राप्त हो सकें।

कांग्रेस सरकार लोगों से किये अपने सभी वादों को पूरा करेगी:प्रतिभा सिंह

शिमला/शैल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि भाजपा जितना भी दुष्प्रचार कर ले उसे इसका कोई भी राजनैतिक लाभ मिलने वाला नही। उन्होंने भाजपा को याद दिलाया है कि जब कर्मचारी ओपीएस की मांग को लेकर सड़को में थे तो उस समय उनके मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उन्हें पैन्शन लेने के लिये चुनाव लड़ने को ललकारा था। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने कार्यकाल में कर्मचारियों की किसी भी मांग को पूरा नही किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में कर्मचारियों के देय भते भी नही दिये गये। प्रदेश सरकार पर 70 हजार करोड़ से अधिक का कर्ज व 12 हजार करोड़ से अधिक की कर्मचारियों की देनदारियां प्रदेश सरकार को भाजपा से विरासत में मिली है।

प्रतिभा सिंह ने कहा है कि भाजपा प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपए देने की कांग्रेस की गारंटी का विरोध कर रही है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग ने भी लाहौल स्पीति की महिलाओं को 1500 की सम्मान निधि जारी रखने को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश की सभी पात्र महिलाओं को यह राशि प्रदान करने को पूरी तरह बचनबद्ध है।

प्रतिभा सिंह ने कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार लोगों से किये अपने सभी वादों को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जिस प्रकार प्रदेश सरकार को अस्थिर करने की असफल कोशिश की अब उसे प्रदेश में लोकसभा की चारों व विधानसभा की छह सीटों पर करारी हार का मुंह देखना पड़ेगा।

प्रतिभा सिंह ने कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार पूरी तरह सुरक्षित है और चुनाव परिणामों के बाद ओर भी मजबूत होगी।

महिलाओं सशक्तिकरण के लिए वर्तमान सरकार ने आरंभ की कई योजनाएं: शांडिल

शिमला/शैल। वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डा. धनी राम शांडिल ने एक प्रेस वक्तव्य में कहा कि वर्तमान प्रदेश कांग्रेस सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में वर्तमान राज्य सरकार ने अनेकों योजनाएँ आरंभ कर उन्हें धरातल पर उतारा है ताकि उन्हें समाज में सशक्त बनाया जा सके तथा वे अपना सम्मानजनक जीवन यापन कर सकें।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपना चुनावी वादा निभाते हुए 18 वर्ष से अधिक की आयु की लड़कियों एवं महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना आरम्भ की है जिसके तहत प्रत्येक पात्र को 1500 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जा रहे हैं। योजना के अंतर्गत फार्म भरने का कार्य शुरू किया गया है तथा महिलाओं को इसका लाभ मिलना आरंभ हो चुका है। भाजपा प्रदेश की महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित करने के लिए बार-बार चुनाव आयोग जा रही है और पेंशन में रोड़े अटका रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2. 42 लाख महिलाओं को 1000 या 1150 रुपये मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल रही थी, जिसे वर्तमान प्रदेश सरकार ने बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया है तथा उन्हें यह राशि मिलना भी शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने विधवा पुनर्विवाह योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता राशि 65 हज़ार रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये की।

डा. धनी राम शांडिल ने कहा कि पुलिस भर्ती में लड़कियों के लिए आरक्षण को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया गया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सीलिंग लैंड होल्डिंग एक्ट, 1972 में परिवार में पुत्र को अलग इकाई माना गया था तथा लड़कियों को अलग इकाई मानने से वंचित रखा गया। परन्तु वर्तमान प्रदेश सरकार ने इस एक्ट में संशोधन कर बेटियों को अलग इकाई बनाया तथा उनके साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त किया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना के तहत एक बेटी के बाद परिवार नियोजन अपनाने वाले परिवार को मिलने वाली 35 हज़ार रुपए की प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर दो लाख रुपए तथा दो बेटियों के बाद परिवार नियोजन पर मिलने वाली 25 हज़ार रुपए की राशि एक लाख रुपए करने का निर्णय लिया है।

डा. धनी राम शांडिल ने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा प्रदेश में मुख्यमंत्री सुख-शिक्षा योजना आरम्भ की जा रही है, जिसके तहत विधवाओं के 27 साल तक के बच्चों की शिक्षा पर होने वाला खर्च प्रदेश सरकार वहन करेगी। विधवा, निराश्रित, तलाकशुदा और अक्षम माता-पिता के सभी पात्र बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक एक हज़ार रुपये प्रतिमाह जमा किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमन्त्री विधवा एवम् एकल नारी आवास योजना के तहत गृह निर्माण की राशि 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये की जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी सहायिका, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर्ज तथा सिलाई अध्यापिकाओं का मानदेय बढ़ाया है।

भाजपा अपने किसी भी मनसूबे में कामयाब नहीं होगी:संजय अवस्थी

शिमला/शैल। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष संजय अवस्थी ने कहा है कि भाजपा अपने किसी भी मनसूबे में कामयाब नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के पास अभी भी पूर्ण बहुमत है और 4 जून को चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस की सरकार ओर भी मजबूत होगी। भाजपा सत्ता में आने के सपने छोड़ दे।

संजय अवस्थी ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को नसीहत देते हुए कहा है कि उन्हें प्रदेश के लोगों की भावना को अपमान करने का कोई अधिकार नही है। प्रदेश के लोगों ने कांग्रेस को पूर्ण बहुमत देकर सत्ता में बिठाया है। कांग्रेस सरकार पूरी तरह स्थिर व मजबूत है और अपना कार्यकाल पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा को प्रदेश के लोग चारों खाने चित करेगी। उन्होंने कहा है कि भाजपा को उसके षडयंत्र का बदला प्रदेश के लोग इन चुनावों में देंगे। उन्होंने कहा कि 4 जून को चुनाव परिणाम पूरी तरह कांग्रेस के पक्ष में आएंगे।

अवस्थी ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक में कहा कि उन्हें भाजपा के किसी भी दुष्प्रचार का कड़ाई से जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि उन्हें भाजपा के धनबल पर कड़ी नजर रखते हुए इसकी पुख्ता जानकारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वॉर रूम को समय पर उपलब्ध करवानी होगी जिससे समय पर इस अनैतिक कार्य पर रोक लग सकें व लोकतंत्र की रक्षा हो सकें। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने धनबल से प्रदेश में चुनाव प्रभावित करने की पूरी कोशिश करेगी और कांग्रेस के सभी लोगों को इस पर अपनी कड़ी नजर रखनी होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जिस प्रकार धनबल पर प्रदेश सरकार को अस्थिर करने की असफल कोशिश की है, ठीक उसी प्रकार यह मतदान के समय मतदाताओं से भी ऐसा ही प्रयास कर सकती है। उन्होंने कहा कि हालांकि प्रदेश के लोग भाजपा के धनबल को पहले ही ठुकरा चुके हैं और वह भाजपा के किसी भी झांसे में आने वाले नही, पर बाबजूद इसके भाजपा के किसी भी षडयंत्र पर नजर रखने की बहुत जरूरत है।

अवस्थी ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में सरकार ने कर्मचारियों को ओपीएस व महिलाओं को 1500 रुपए की सम्मान राशि जारी कर प्रदेश के जनकल्याण के प्रति अपनी बचनबद्धता को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने 15 माह के कार्यकाल में 22 हजार से अधिक बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किये है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की जनकल्याण की नीतियों व निर्णयों को घर घर तक पहुंचाया जाना चाहिए। उन्होंने पार्टी के सभी पदाधिकारियों को एकजुटता के साथ जो भी जिम्मेवारियों उन्हें दी गई है उनको पूरी निष्ठा व ईमानदारी से पूरा करने को कहा है। उन्होंने कहा कि जिस ब्लॉक में पार्टी का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहेगा उसके सभी पदाधिकारियों संगठन की ओर से विशेष मान सम्मान दिया जाएगा।

मात्र सवा साल में 'गुड गर्वनेंस' की मिसाल बनी सुक्खू सरकार: धर्माणी

शिमला/शैल। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार मात्र सवा साल के कार्यकाल में 'गुड गर्वनेंस' की मिसाल बनी है। उन्होंने कहा कि राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से लंबित मामलों को निपटाने में राज्य सरकार को अभूतपूर्व सफलता मिली है। आम लोगों को राहत प्रदान करते हुए फ़रवरी 2014 तक इस विशेष मुहिम के तहत इंतकाल के 1.05 लाख से अधिक तथा तकसीम के सात हजार मामलों का निपटारा किया गया है। यह आँकड़े अपने आप में राजस्व लोक अदालतों के आयोजन की सफलता साबित कर रहे हैं।

धर्माणी ने कहा कि राजस्व लोक अदालतों के आयोजन की राज्य सरकार की पहल का आज हिमाचल प्रदेश की जनता खुले दिल से स्वागत कर रही है और इसके लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को धन्यवाद दे रही है। हिमाचल में कहा जाता था कि राजस्व मामले पीढ़ियों तक भुगतने पड़ते हैं लेकिन वर्तमान राज्य सरकार ने इन कहावतों को बदल दिया है, जिसके लिए राजस्व क़ानूनों में संशोधन किया गया, ताकि राजस्व मामलों के निपटारे में तेज़ी लाई जा सके और लोगों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें। उन्होंने कहा कि वर्षों तक हिमाचल प्रदेश के लोगों की इस पीड़ा को किसी सरकार ने नहीं समझा और न ही उनके दर्द को दूर करने के लिए प्रयास किए, लेकिन वर्तमान राज्य सरकार का एकमात्र उद्देश्य जन सेवा है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा, विशेष रुप से उस वर्ग की सेवा करने की है, जिस पर आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया।

राजेश धर्माणी ने कहा कि मात्र सवा साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार ने उन तबकों की आवाज़ बनाने का प्रयास किया है, जिसके बारे में किसी सरकार ने कभी विचार नहीं किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के फैसलों में जन सेवा की भावना साफ़ झलकती है। वर्तमान राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना आरंभ की, महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन प्रदान की। यही नहीं, विधवा और एकल नारियों के सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार ने अनेकों योजनाएं आरंभ की हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने मुख्यमंत्री सुख-शिक्षा योजना शुरू की है, जिसके तहत विधवाओं के 27 साल तक के बच्चों की शिक्षा पर होने वाला खर्च प्रदेश सरकार वहन कर रही है। विधवा, निराश्रित, तलाकशुदा और अक्षम माता-पिता के सभी पात्र बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक एक हज़ार रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमन्त्री विधवा एवम् एकल नारी आवास योजना के तहत गृह निर्माण की राशि 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये की जाएगी।

उन्होंने कहा कि सवा साल के छोटे से कार्यकाल के भीतर वर्तमान राज्य सरकार ने न सिर्फ दस में से पांच गारंटियों को पूरा किया है, बल्कि इससे आगे बढ़कर काम कर जन कल्याण का नया अध्याय लिखा है।

आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 8.40 करोड़ रुपये जब्तियां

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव और उप-चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस और अन्य विभागों द्वारा 8.40 करोड़ रुपये की अवैध शराब, नकदी, आभूषण आदि जब्त किये गये हैं। यह जानकारी निर्वाचन विभाग के प्रवक्ता ने दी।

उन्होंने बताया कि राज्य आबकारी एवं कराधान और पुलिस विभागों ने 5. 80 करोड़ रुपये मूल्य की 396655 लीटर शराब जब्त की है। प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस विभाग ने अब तक 74.63 लाख रुपये की 37 किलोग्राम चरस, 1.08 करोड़ रुपये कीमत की 1. 55 किलोग्राम हेरोइन तथा 25 लाख रुपये की नकदी भी जब्त की है। उन्होंने कहा कि अब तक लगभग 3. 35 लाख रुपये के सोने व चांदी के आभूषण भी जब्त किये जा चुके हैं।

जब तक करोड़ों लोग भूखे और अज्ञानी रहेंगे, मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को विश्वासघाती मानूंगा जो उनकी कीमत पर शिक्षित हुआ है और उनकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। ..... स्वामी विवेकानन्द

सम्पादकीय

सह प्रभारी का पलायन प्रदेश के लिए बड़ा संकेत

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और हिमाचल के सहप्रभारी तेजिन्द्र बिट्टू कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गये हैं। वैसे तो इन चुनावों से कई राज्यों में कई नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा या अन्य दलों में शामिल हो गये हैं। नेताओं का इस तरह दल बदलना अपने में कई सवाल खड़े कर जाता है। एक समय यह निश्चित रूप से दलों के लिये कई बौद्धिक सवाल खड़े करेगा। इस समय इन लोकसभा चुनावों में भाजपा ने दूसरे दलों से सेन्ध लगाकर करीब एक लाख लोगों को भाजपा में शामिल करने का लक्ष्य रखा है। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा तो बहुत अच्छे से भाजपा में चल रहा है। एक देश एक चुनाव का जो वायदा इस बार भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में कर रखा है उसे अब आने वाले दिनों में एक दल और एक नेता की ओर बढ़ने का पहला कदम माना जा रहा है। भाजपा की इस नीति का कालान्तर में देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह तो आने वाला समय ही बतायेगा। लेकिन इस सम्भावित परिदृश्य में आज क्या कदम उठाये जाने चाहिए यह विचार करना महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरे दलों में सेन्ध लगाने का जो घोषित लक्ष्य रखा गया है उसे पूरा करने के लिये दूसरे दलों की सरकारें गिराना भी इस नीति का एक चरण हो सकता है। क्योंकि जब दूसरे दल स्थिर सरकारें ही नहीं दे पायेंगे तो लोगों का उनसे मोह भंग होना स्वभाविक है।

भारत एक बहुधर्मी, बहुभाषी और बहुजातीय देश है। इतने बड़े देश में एक ही दल की एक ही नेता के तहत सरकार की कल्पना तक करना भयावह लगता है। क्योंकि एक ही नेता सर्वज्ञ नहीं हो सकता और जब एक नेता को ईश्वरीय संज्ञाओं से अलंकृत करने का चलन शुरू हो जाये तो वह अनिष्ट का पहला संकेत माना जाता है। इस समय प्रधानमंत्री मोदी को बहुत लोग ईश्वरीय संबोधन से संबोधित करने लग पड़े हैं। स्वभाविक है कि जब एक नेता को ऐसे संबोधित किया जाने लग जायेगा तब दूसरे दलों में पलायन का मार्ग प्रशस्त होना शुरू हो जायेगा। चुनावों के बीच हो रहा पलायन कुछ इसी तरह के संकेत दे रहा है। ऐसे पलायन को रोकना दलों के शीर्ष नेतृत्व का दायित्व हो जाता है। इस समय भाजपा और कांग्रेस ही देश में दो सबसे बड़े दल हैं और यह इनके शीर्ष नेतृत्व की जिम्मेदारी हो जाती है कि यह अपने यहां हो रहे पलायन को रोकें।

यह पलायन रोकने के लिए पलायन करने आने वाले नेताओं द्वारा अपने-अपने दलों के नेतृत्व पर लगाये जा रहे आरोपों को जानना और समझना आवश्यक हो जाता है। इसके लिये यदि कांग्रेस छोड़कर गये नेताओं के आरोपों को सामने रखा जाये तो स्थिति कुछ सरलता से सामने आ सकती है। अभी तेजिन्द्र बिट्टू ने कांग्रेस छोड़ी है और उसने आरोप लगाया है कि संगठन में चार-पांच सत्ता केंद्र हो गये हैं और उनमें आपसी तालमेल का अभाव है। हिमाचल में भी छः विधायक कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गये हैं। यह लोग लम्बे अरसे से संगठन के भीतर अपने सवाल रख रहे थे। जब संगठन में उनकी बात नहीं सुनी गयी तब मीडिया मंचों के माध्यम से भी इन्होंने अपनी बात सार्वजनिक की। लेकिन तब भी दिल्ली से लेकर शिमला तक किसी ने उनकी बात नहीं सुनी और परिणाम सामने आ गया। यहां भी समानांतर सत्ता केंद्र स्थापित होने तथा उनमें तालमेल का अभाव रहने का आरोप था। यह सत्ता केंद्र अभी भी यथास्थिति कायम हैं। यदि समय रहते स्थितियों में सुधार न हुआ तो परिणाम भयानक हो सकते हैं। तेजिन्द्र बिट्टू का पलायन प्रदेश के लिये एक बड़ा संकेत है।

भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान ने श्री राम लला के मस्तक पर सूर्य की रोशनी डालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान ने अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सूर्य तिलक परियोजना के अंतर्गत चैत्र मास में श्री राम नवमी के अवसर पर दोपहर 12 बजे श्री राम लला के मस्तक पर सूर्य की रोशनी डाली गयी। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान की टीम ने सूर्य की स्थिति, प्रकाशीय प्रणाली के डिजाइन व अनुकूलन की गणना की और साइट पर एकीकरण और सरेखण का प्रदर्शन किया।

श्री राम नवमी उत्सव की अंग्रेजी कैलेंडर तिथि चंद्र कैलेंडर के अनुसार हर वर्ष बदलती है। इसलिए, हर वर्ष श्री राम नवमी के दिन आकाश पर सूर्य की स्थिति बदल जाती है। विस्तृत गणना से पता चलता है कि श्री राम नवमी की अंग्रेजी कैलेंडर की तारीख हर 19 वर्ष में दोहराई जाती है। इन दिनों आकाश में सूर्य की स्थिति की गणना के लिए खगोल विज्ञान में विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है।

आईआईए टीम ने 19 वर्षों के एक चक्र के लिए श्री राम नवमी के कैलेंडर दिनों की पहचान के लिए गणना की अगुवाई की। इसके बाद इसकी पुनरावृत्ति, राम नवमी की कैलेंडर तिथियों पर आकाश में अवस्थिति का अनुमान लगाया।

आईआईए टीम के लोगों ने मंदिर के शीर्ष से मूर्ति के ललाट के ऊपरी हिस्से तक सूरज की किरण के पहुंचने, लगभग 6 मिनट तक मूर्ति पर पर्याप्त रोशनी के लिए इस पूरी प्रणाली में दर्पण और लेंस के आकार एवं संरचना, मूर्ति, लेंस और दर्पण धारक असेंबली का ऑप्टो-मैकेनिकल डिजाइन के साथ-साथ आकाश में सूर्य की अवस्थिति के अनुसार पहले दर्पण की स्थिति को बदलने के लिए मैनुअल तंत्र एक ऑप्टो-मैकेनिकल सिस्टम का अनुमान के बारे में भी डिजाइन तैयार करने के कार्य का नेतृत्व किया। तंत्र की कार्यप्रणाली में विभिन्न मात्राओं तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण डिजाइन संबंधी अनुकूलन के साथ-साथ सिमुलेशन भी किए गए।

चूंकि मंदिर निर्माण का कार्य फिलहाल पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है, आईआईए विशेषज्ञों ने मौजूदा संरचना के अनुरूप डिजाइन को संशोधित किया और छवि अनुकूलन किया। 4 दर्पणों और 2 लेंसों वाला यह डिज़ाइन 17 अप्रैल 2024 को सूर्य तिलक के लिए निष्पादित किया गया है। आईआईए के तकनीकी विशेषज्ञों ने साइट पर सिस्टम के परीक्षण, संयोजन, एकीकरण और सत्यापन में भाग लिया। 17 अप्रैल 2024 को प्रथम सूर्य तिलक से पहले राम मंदिर में ट्रायल रन के दौरान आईआईए के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा दर्पण और लेंस का महत्वपूर्ण सरेखण किया गया था।

अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना में ऑप्टो-मैकेनिकल सिस्टम को सीबीआरआई ने अंजाम दिया है। यंत्र का निर्माण ऑप्टिका, बैंगलोर ने किया है।

4 दर्पणों और 4 लैंसों के साथ सूर्य तिलक के अंतिम डिज़ाइन का उपयोग मंदिर के पूर्ण निर्माण के बाद दर्पणों और लैंसों को उनके स्थायी स्थान में रखकर किया जाएगा। उपरोक्त तंत्र को पंचाग के हिसाब से रामनवमी की तिथि 1-2 दिन बदलने पर भी काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। एक परिवर्तन से मूर्ति पर लगे स्थान की अवधि बदल जाएगी। बादल या बारिश के कारण धूप नहीं होने पर तंत्र काम नहीं करेगा। प्रत्येक वर्ष राम नवमी से पहले दर्पण को मैन्युअल रूप से वार्षिक शिफ्ट किया जाएगा। होल्डरों पर लगे लैंस और दर्पण पहुंच योग्य हैं और इन्हें समय-समय पर साफ किया जा सकता है।

यंत्र का निर्माण ऑप्टिका, बैंगलोर द्वारा किया गया है और साइट पर ऑप्टो-मैकेनिकल सिस्टम का कार्यान्वयन सीएसआईआर -सीबीआरआई द्वारा किया जा रहा है।

निर्वाचन आयोग ने चुनाव के हर चरण से पहले गर्मी की स्थिति पर नजर रखने के लिए कार्य बल गठित किया

शिमला। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक ने निर्वाचन आयोग को सूचित किया कि इस महीने की 26 तारीख को होने वाले आम चुनाव के दूसरे चरण में गर्मी की लहर को लेकर कोई बड़ी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरे चरण के मतदान वाले 13 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में मौसम सामान्य रहने का पूर्वानुमान लगाया गया है। देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान और गर्मी की लहरों की रिपोर्टों के मद्देनजर, आयोग ने बदलते मौसम को समझने और आम चुनावों के दौरान गर्म मौसम के कारण किसी भी जोखिम को कम करने के उपायों पर चर्चा करने के लिए संबंधित एजेंसियों के साथ बैठक की।

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) के अपर सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के विभाग प्रमुख और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के महानिदेशक ने भाग लिया।

अप्रैल 21-25, 2024 के लिए मौसम का पूर्वानुमान बैठक के दौरान निम्नलिखित निर्णय लिये गये:

1. आवश्यक हुआ तो ईसीआई, आईएमडी, एनडीएमए और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रलय के अधिकारियों का एक कार्य बल मौसम में किसी भी प्रकार के बदलाव और शमन उपायों के लिए मतदान के प्रत्ध्येक चरण से पांच दिन पहले गमह्न की लहर व आर्द्रता के प्रभाव की समीक्षा करेगा।

2. आयोग ने गृह मंत्रलय को निर्देश दिया है कि वह राज्यों में स्वास्थ्य अधिकारियों को आवश्यक हिदायत दे कि वे चुनाव संचालन को प्रभावित करने वाली लू की स्थिति के लिए तैयारी रखें और सहायता प्रदान करें।

3. आयोग 16 मार्च, 2024 की अपनी मौजूदा सलाह के अनुसार मतदान केन्द्रों पर शामियाना, पीने के पानी, पंखे और अन्य आवश्यक न्यूनतम सुविधाओं आदि सहित पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए राज्य के सीईओ के साथ अलग से समीक्षा करेगा।

4. मतदान केन्द्र क्षेत्रों में गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए एहतियाती उपायों (क्या करें और क्या न करें) के लिए जनता के बीच आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) गतिविधियां की जाएंगी।

आयोग मौसम रिपोर्टों पर बारीकी से नजर रख रहा है और मतदान कर्मियों व सुरक्षा बलों, उम्मीदवारों और राजनीतिक दल के नेताओं के साथ-साथ मतदाताओं की सुविधा एवं हितों को सुनिश्चित करेगा।

सभी दलों/उम्मीदवारों के साथ समान व्यवहार, समान अवसर प्रदान करना एकमात्र पथ प्रदर्शक

आदर्श आचार संहिता एक नियामक ढांचा है, हालांकि सख्त मायनों में कानूनी समर्थन के बिना, एक समान अवसर सुनिश्चित करने और नैतिक प्रचार के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए इसे तैयार किया गया है। आयोग ने समान अवसर और चुनाव प्रचार की स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखने की जटिल गतिशीलता से पार पा लिया है। उल्लंघनों का तुरंत और निर्णायक समाधान करके, भारत का चुनाव आयोग पारदर्शिता, निष्पक्षता, जवाबदेही और समान अवसर के लोकतांत्रिक आदर्शों को मजबूत करता है। चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता को कायम रखना सर्वोपरि है।

शिमला। अपनी तरह के पहले कार्य में, जिसके लिए आयोग किसी भी तरह से बाध्य नहीं है, अपने वायदे के अनुसार पारदर्शिता बरतते हुए, निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के अमल में आने के पहले महीने के दौरान, कुछ कार्यो के विवरण के साथ इसे सार्वजनिक करने का फैसला किया है, ताकि समय-समय पर कुछ लोगों की गलतफहमियों और आक्षेपों को दूर किया जा सके और इन्हें रोका जा सके।
स्थिति इस प्रकार है, जो संहिता की शेष अवधि के लिए भी लागू होती है।

आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू होने के बाद एक महीना पूरा होने पर, भारत का निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों द्वारा संहिता के अनुपालन से मोटे तौर पर संतुष्ट है और विभिन्न दलों और उम्मीदवारों द्वारा अभियान काफी हद तक व्यवस्थित चल रहा है।

साथ ही, आयोग ने कुछ परेशान करने वाली प्रवृत्तियों पर कड़ी नजर रखने और कुछ पथभ्रष्ट उम्मीदवारों, नेताओं और कार्य प्रणालियों पर पहले से कहीं अधिक विशेष नजर रखने का निर्णय लिया है।

आयोग ने विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले दलों के नेताओं को नोटिस जारी करके महिलाओं की गरिमा और सम्मान के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए पार्टी प्रमुखों/अध्यक्षों पर जवाबदेही तय करने में एक कदम आगे बढ़ गया कि उनकी पार्टी के नेता और प्रचारक इस तरह की अनादरपूर्ण और अपमानजनक टिप्पणियों का सहारा न लें। आदर्श आचार संहिता जवाबदेही, पारदर्शिता और दृढ़ता के अनुरूप लागू की गई है जैसा कि सीईसी राजीव कुमार ने पहले वायदा किया था।

आयोग संवैधानिक समझ से निर्देशित था जब उसे राजनीतिक व्यक्तियों से जुड़ी स्थितियों के साथ प्रस्तुत किया गया था जो आपराधिक जांच के आधार पर न्यायालयों के सक्रिय विचार और आदेशों के अधीन थे। हालांकि आयोग राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए समान अवसर और प्रचार के अधिकार की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, लेकिन उसने ऐसा कोई भी कदम उठाना सही नहीं पाया है जो कानूनी न्यायिक प्रक्रिया को ओवरलैप या ओवरराइड कर सके।

आदर्श संहिता को लागू करने में, आयोग को अपनी अनिवार्य जिम्मेदारी, कानूनी अचल सम्पत्ति, संस्थागत समझ, समानता और लेनदेन में पारदर्शिता के लिए निर्देशित किया गया है चाहे संबंधित व्यक्तियों का ओहदा और प्रभाव कुछ भी हो या उनकी राजनीतिक संबद्धता कुछ भी हो।

लोकसभा चुनावों की घोषणा के साथ 16 मार्च, 2024 को आदर्श संहिता लागू हुई। तब से चुनाव आयोग ने यह सुनिश्चित करने के लिए त्वरित और हितकर कारवाई की है कि समान अवसर में गड़बड़ी न हो और प्रचार में चर्चा अस्वीकार्य स्तर तक न गिरे।

एक महीने की अवधि के दौरान, 07 राजनीतिक दलों के 16 प्रतिनिधिमंडलों ने आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन और संबंधित मामलों पर अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए आयोग से मुलाकात की। राज्यों में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर कई प्रतिनिधिमंडल मिले।

सभी राजनीतिक दलों के साथ समान व्यवहार किया गया है, अल्प सूचना पर भी सभी को समय दिया गया और उनकी शिकायतों को धैर्यपूर्वक सुना गया।

सीईसी राजीव कुमार के नेतृत्व वाला आयोग ईसी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के साथ रोजाना दोपहर 12 बजे एमसीसी के कथित उल्लंघन के देशव्यापी लंबित मामलों की निगरानी करता है।

चुनावों की घोषणा से पहले, सभी डीएम/कलेक्टर/डीईओ और एसपी को बिना किसी समझौते के मॉडल कोड लागू करने के लिए आयोग द्वारा विशेष रूप से और सीधे जागरूक किया गया था। सीईसी राजीव कुमार ने दिल्ली में ईसीआई प्रशिक्षण संस्थान, आईआईआईडीईएम में 10 बैचों में 800 से अधिक डीएम/डीईओ को व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित किया था। क्षेत्र के अधिकारियों ने इस कार्य में काफी हद तक खुद को मुक्त कर लिया है।

मॉडल कोड की पिछली एक महीने की अवधि के दौरान समान अवसर बनाए रखने के लिए ईसीआई के कुछ निर्णय इस प्रकार हैं:

विभिन्न राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा ईसीआई और राज्यों के स्तर पर लगभग 200 शिकायतें दर्ज की गई हैं। इनमें से 169 मामलों में कारवाई की गयी है।

शिकायतों का विवरण इस प्रकार है: भाजपा से प्राप्त कुल शिकायतें 51 थीं, जिनमें से 38 मामलों में कारवाई की गई है। कांग्रेस की ओर से 59 शिकायतें थीं, जिनमें से 51 मामलों में कारवाई की गई। अन्य पक्षों से प्राप्त शिकायतें 90 थीं, जिनमें से 80 मामलों में कारवाई की गई है।

छः राज्यों गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मुख्यमंत्रियों के प्रधान सचिव के रूप में दोहरे प्रभार वाले अधिकारियों को स्वतः संज्ञान से हटाया गया, क्योंकि उनके पास गृह/सामान्य प्रशासन विभाग का भी प्रभार था। इसका उद्देश्य चुनाव से संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों, डीएम/डीईओ/आरओ और एसपी को मुख्यमंत्री कार्यालयों से दूर करना था।

पश्चिम बंगाल के डीजीपी को स्वतः संज्ञान से हटाया गया क्योंकि उन्हें पिछले चुनावों में भी चुनाव ड्यूटी से रोका गया था।

चार राज्यों गुजरात, पंजाब, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) और पुलिस अधीक्षक (एसपी) के रूप में नेतृत्व पदों पर तैनात गैर-कैडर अधिकारियों का स्वतः स्थानांतरण।

पंजाब, हरियाणा और असम में निर्वाचित राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ रिश्तेदारी या पारिवारिक जुड़ाव के कारण अधिकारियों का स्वतः स्थानांतरण।

चुनाव की घोषणा के बाद, कांग्रेस और आप की शिकायत पर, व्हाट्सएप पर भारत सरकार के विकसित भारत संदेश का प्रसारण रोकने के लिए एमईआईटीवाई को निर्देश दिया गया।

कांग्रेस और आप की शिकायत पर, सरकारी/सार्वजनिक परिसरों को विकृत करने पर ईसीआई के निर्देशों का तत्काल प्रभाव से अनुपालन करने के लिए सभी राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को निर्देश।

डीएमके की शिकायत पर भाजपा मंत्री शोभा करंदलाजे के खिलाफ रामेश्वर ब्लास्ट कैफे पर असत्यापित आरोपों के लिए एफआईआर दर्ज की गई।

आईएनसी की शिकायत पर, डीएमआरसी ट्रेनों और पेट्रोल पंप, राजमार्गो आदि से होर्डिंग्स, फोटो और संदेशों सहित सरकारी/सार्वजनिक परिसरों को विकृत करने पर ईसीआई के निर्देशों के अनुपालन के लिए कैबिनेट सचिव को निर्देश।

कांग्रेस की शिकायत पर, केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखरन द्वारा अपने हलफनामे में संपत्ति की घोषणा में किसी भी बेमेल के सत्यापन के लिए सीबीडीटी को निर्देश।

ममता बनर्जी के प्रति आपत्तिजनक एवं अपमानजनक टिप्पणी के लिए एआईटीएमसी की शिकायत पर भाजपा नेता दिलीप घोष को नोटिस।

भाजपा की शिकायत पर, सुप्रिया श्रीनेत और सुरजेवाला, दोनों को क्रमशः कंगना रनौत और हेमा मालिनी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों के लिए नोटिस।

नरेंद्र मोदी के प्रति डीएमके नेता अनिता आर राधाकृष्णन द्वारा की गई टिप्पणी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।

दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में प्रकाशकों का नाम बताये बिना होर्डिंग और बिलबोर्ड में गुमनाम विज्ञापनों के खिलाफ आम आदमी पार्टी की शिकायत पर कानून में अंतर को पाटने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। होर्डिंग्स को शामिल करके मौजूदा कानून में 'पैम्फलेट और पोस्टर' के अर्थ को व्यापक आयाम देते हुए, सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें प्रचार में जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए होर्डिंग्स सहित मुद्रित चुनाव-संबंधी सामग्री पर प्रिंटर और प्रकाशक की स्पष्ट पहचान सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

कांग्रेस की शिकायत पर, दिल्ली में नगर निगम अधिकारियों को विभिन्न कॉलेजों से स्टार प्रचारकों के कटआउट हटाने के निर्देश जारी किए गए हैं।

नागरिकों की उल्लंघन संबंधी शिकायतों पर आयोग के पोर्टल सी विजिल पर कुल 2,68,080 शिकायतें दर्ज की गई हैं। इनमें से 2,67,762 मामलों में कारवाई की गई और 92 प्रतिशत मामलों का समाधान औसतन 100 मिनट से भी कम समय में किया गया। सीविजिल की प्रभावशीलता के कारण, अवैध होर्डिंग्स, संपत्ति को विकृत करने, दिए गए समय से अधिक समय तक प्रचार करने औरअनुमति से अधिक वाहनों की तैनाती में काफी कमी आई है।

भीषण गर्मी के बावजूद लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में भारी मतदान

शिमला। आम चुनाव 2024 के पहले चरण के मतदान में भीषण गर्मी के बावजूद भारी मतदान दर्ज किया गया। मतदान काफी हद तक शांतिपूर्ण रहा और विभिन्न क्षेत्रों के मतदाताओं ने नागरिक जिम्मेदारी व गौरव का शानदार प्रदर्शन करते हुए उत्साहपूर्वक भाग लिया। आम चुनाव 2024 के पहले चरण में, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की राज्य विधानसभाओं के लिए मतदान के साथ-साथ 18वीं लोकसभा के चुनाव के लिए 10 राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में मतदान पूरा हो गया है। आयोग ने पहले चरण के मतदाताओं और पूरी चुनाव मशीनरी को धन्यवाद दिया।

शाम 7 बजे तक 21 राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में मतदान का संभावित आंकड़ा 60 प्रतिशत से अधिक बताया गया है। सभी मतदान केंद्रों से रिपोर्ट प्राप्त होने पर मतदान प्रतिशत बढ़ने की संभावना है, क्योंकि कई निर्वाचन क्षेत्रों में शाम 6 बजे तक मतदान निर्धारित है। साथ ही, मतदान का समय समाप्त होने तक मतदान केंद्रों पर पहुंचने वाले मतदाताओं को अपना वोट डालने की अनुमति दी जाती है। अंतिम आंकड़े कल फॉर्म 17ए की जांच के बाद पता चलेंगे।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त (ईसी) ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के नेतृत्व में आयोग ने निर्वाचन सदन में ईसीआई मुख्यालय से सभी निर्वाचन क्षेत्रों में चरण 1 में मतदान की प्रगति की लगातार निगरानी की। इस उद्देश्य के लिए मुख्यालय में एक अत्याधुनिक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया था। राज्य/जिला स्तर पर भी ऐसे ही नियंत्रण कक्ष बनाये गये।

नियंत्रण कक्ष, पश्चिम बंगाल व्यापक तौर पर शांतिपूर्ण और अनुकूल माहौल की पृष्ठभूमि में, देश के विविधतापूर्ण मतदाताओं ने लोकतंत्र की जीवंत तस्वीरें पेश कीं। भीड़-भाड़ वाले शहरी केंद्रों से लेकर दूरदराज के गांवों तक, मतदान केंद्रों पर पीढ़ियों और विभिन्न पृष्ठभूमि वाले मतदाताओं का रंगारंग जमावड़ा देखा गया। आयोग और उसके अधिकारियों द्वारा क्षेत्र में सावधानीपूर्वक योजना व कार्यान्वयन के आधार पर निर्बाध मतदान की व्यवस्था की गई थी।

जनजातीय भीतरी इलाकों में मतदान की सुविधा पर आयोग के ध्यान के साथ, छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में समुदायों ने शांति और लोकतंत्र का रास्ता चुनते हुए, बुलेट के बजाये बैलट (मतपत्र) की शक्ति को अपनाया। लोकसभा चुनाव में बस्तर के 56 गांवों के मतदाताओं ने पहली बार अपने ही गांव में बने मतदान केंद्र पर वोट डाले। बीजापुर के मॉडल मतदान केंद्र पीसी-163 में मतदाताओं को चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिलता देखा गया। गढ़चिरौली- चिमुर, महाराष्ट्र से एक अन्य उदाहरण में हेमलकासा बूथ पर स्थानीय जनजातीय बोली का उपयोग किया गया था, जिसमें सभी संबंधित विवरण शामिल था। बिहार के बोधगया में, बौद्ध भिक्षुओं को मुस्कुराते हुए और अपनी उंगलियों पर गौरव का प्रदर्शन करते हुए देखा गया।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में आदिवासी समुदाय के मतदाता बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए बाहर निकले। ग्रेट निकोबार की शोम्पेन जनजाति ने आमचुनाव-2024 में पहली बार वोट डालकर इतिहास रच दिया। मिजोरम में, एक बुजुर्ग जोड़े ने एक साथ मतदान करने का अपना संकल्प दोहराया। अरुणाचल प्रदेश में, एक बुजुर्ग महिला घर पर मतदान की सुविधा होने के बावजूद अपनी इच्छा से पैदल चलकर मतदान केंद्र तक पहुंची।

देश के अधिकांश हिस्सों में मतदाताओं ने गर्मी का सामना किया, जबकि अन्य हिस्सों में मतदाता भारी बारिश के बीच धैर्यपूर्वक अपनी बारी की प्रतीक्षा करते रहे। प्रत्येक मतदान केंद्र पर ईसीआई द्वारा दी गई सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं उनके लिए बहुत मददगार थीं।

नगालैंड में मॉडल मतदान केंद्र

मतदाता भारतीय संस्कृति की समृद्ध झलक दिखाने वाली रंग-बिरंगी पोशाकें पहनकर आए और गर्व से स्याही लगी अंगुलियों के साथ अपनी सेल्फी ली, जो नागरिकों के कर्तव्य के निष्पादन का प्रतीक है।

आम चुनाव 2024 के सात चरण में, 21 राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के 102 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में आज मतदान संपन्न हुआ। उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, नगालैंड, मिजोरम, तमिलनाडु और केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप सहित राज्यों ने अपनी मतदान प्रक्रिया पूरी कर ली। निर्वाचन आयोग, आम चुनाव 2024 के बाद के चरणों में एक सुचारू, पारदर्शी और समावेशी चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है।

राज्यवार आंकड़े यह हैं।

Estimated Poll Turnout (Phase - 1) at 07:00 PM

Sl. No.	State	Latest Updated Poll %
1	AndamanNicobar	56.87
2	ArunachalPradesh	65.46
3	Assam	71.38
4	Bihar	47.49
5	Chattisgarh	63.41
6	JammuKashmir	65.08
7	Lakshwdeep	59.02
8	MadhyaPradesh	63.33
9	Maharashtra	55.29
10	Manipur	68.62
11	Meghalaya	70.26
12	Mizoram	54.18
13	Nagaland	56.77
14	Puducherry	73.25
15	Rajasthan	50.95
16	Sikkim	68.06
17	TamilNadu	62.19
18	Tripura	79.90
19	UttarPradesh	57.61
20	Uttarakhand	53.64
21	WestBengal	77.57

सरकार उठाएगी पीड़ित बिटिया के इलाज का खर्च:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पालमपुर में बीते दिनों हुई हृदय

विदारक घटना की पीड़िता के परिवार के लोगों से मुलाकात की। धर्मशाला से सुजानपुर आते समय मुख्यमंत्री सुलह में नाल्टी दा पुल के पास एकत्रित लोगों से मिले और उनकी बात सुनी। पीड़िता के माता-पिता पीजीआई चंडीगढ़ में बेटी के साथ हैं, इसलिए परिवार के अन्य लोगों ने मुख्यमंत्री को पूरी घटना के बारे में बताया। उन्होंने हमलावर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कारवाई की मांग की।

मुख्यमंत्री ने उनकी बात सुनने के बाद कहा कि पालमपुर की दर्दनाक घटना से दुखी हूँ। पीड़ित बिटिया के इलाज का पूरा खर्च हिमाचल सरकार उठाएगी। सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। एसपी कांगड़ा को जरूरी दिशा-निर्देश दिए हैं। घटनाक्रम के बाद से रोजाना पुलिस अधिकारियों से अपडेट लिया जा रहा है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। केवल गिरफ्तारी हमारा उद्देश्य नहीं है। ऐसी घटनाओं को क्यों अंजाम दिया जा रहा है, उस दिशा की तरफ बढ़ने की जरूरत है। हम जानना चाह रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त है, किसी को कानून तोड़ने नहीं दिया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ खेल मंत्री यादविंदर गोमा, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार, कैबिनेट रैंक सुनील शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान आईटी सलाहकार कैबिनेट रैंक गोकुल बुटेल, ओएसडी रितेश कपरेट, चेयरमैन संजय चौहान, विशाल चंबियाल इत्यादि मौजूद रहे।

सरकार कर रही युवाओं, किसानों के हितों की रक्षा:हर्षवर्धन

शिमला/शैल। भाजपा पर निशाना साधते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में वर्तमान प्रदेश सरकार अन्नदाताओं और युवाओं के हितों की रक्षा करने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि युवाओं और किसानों के हकों की पैरवी करने वाले भाजपा नेता यह भूल रहे हैं कि पिछली भाजपा सरकार ने किसानों और युवाओं को हाशिए पर धकेलना का काम किया।

हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि किसानों के शुभचिंतक होने का ढोंग करने वाले भाजपा नेता यह भूल रहे हैं कि केंद्र की भाजपा सरकार के किसान विरोधी बिलों के विरोध में किसानों ने देश का सबसे बड़ा किसान आन्दोलन चलाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के लिए किसानों और पशुपालकों का उत्थान प्राथमिकता में शुमार हैं, इसलिए सरकार ने पशुपालकों और किसानों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने गाय के दूध के समर्थन मूल्य में ऐतिहासिक वृद्धि करते हुए इसे 32 रुपये से बढ़कर 45 रुपये प्रति लीटर तथा भैंस के दूध के समर्थन मूल्य को 47 रुपए से बढ़कर 55 रुपये प्रति लीटर किया गया है। उन्होंने कहा कि दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है, जिससे पशुपालकों की आय में बढ़ौतरी हो रही है। साथ ही, प्रदेश के पशुपालकों को लाभान्वित करने के लिए जिला कांगड़ा के डगवार में लगभग 226 करोड़ रुपये की लागत से 'स्टेट ऑफ द आर्ट' दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र लगाया जायेगा जिससे दूध के अनेक तरह के उत्पाद तैयार कर पशुपालकों के दूध का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।

उद्योग मंत्री ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार यह भलीभांति जानती है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करके ही आत्मनिर्भर हिमाचल के सपने को साकार किया जा सकता है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्ट - अप योजना के तहत लगभग 36 हजार किसानों को प्रा तिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देते हुए सरकार ने प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं को 40 रुपये और मक्की को 30 रुपये प्रति किलोग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का फैसला लिया है जो पूरे देश में गेहूं और मक्की पर दिया जाने वाला सबसे अधिक समर्थन मूल्य है। उन्होंने कहा कि बागवानों को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से सेब, आम और नींबू प्रजाती के फलों के समर्थन मूल्य में 1.50 रुपये की ऐतिहासिक वृद्धि कर 10.50 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये प्रतिकिलो किया गया है। इसके साथ ही इतिहास में पहली बार हिमाचल प्रदेश के सेब बागवानों का सेब किलो के हिसाब से बिका, जिससे उन्हें फ़ायदा हुआ। प्रदेश सरकार ने अगले सीज़न से हिमाचल प्रदेश में यूनिवर्सल कार्टन को लागू करने का निर्णय लिया है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार के यह निर्णय दर्शाते हैं कि प्रदेश सरकार किसानों और बागवानों को प्राथमिकता प्रदान कर उनका कल्याण और उत्थान सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को किसानों और बागवानों के हितों में लिए जा रहे निर्णय रास नहीं आ रहे और कांग्रेस को मिल रहे अपार जन समर्थन से वे बौखलाहट में अनाप-शनाप बयानबाजी कर रहे हैं।

सेब बाग़बानों को बर्बाद करने पर तुली केंद्र सरकार:भंडारी

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष निगम भंडारी ने कहा है कि केंद्र सरकार निरंतर आयात शुल्क में कमी कर हिमाचल प्रदेश के सेब बाग़बानों को बर्बाद करने पर तुली है। उन्होंने कहा कि आयात शुल्क घटने से विदेश सेब का आयात बढ़ रहा है, जिससे हिमाचली सेब का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सेब की आर्थिक 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है और लाखों परिवार इस कारोबार से प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से जुड़े हैं। किसान लगातार आयात शुल्क को 100 फ़ीसदी करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार इसे लगातार घटा रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है।

हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस ने कहा कि सस्ते विदेशी सेब के कारण इस बार कोल्ड स्टोर में सेब रखने वाले बाग़वानों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि विदेशी सेब के कारण कोल्ड स्टोर का इस्तेमाल करने वाले बागवानों को 800-1200 रुपए प्रति पेटी का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि अमेरिका, ईरान, अफगानिस्तान, न्यूज़ीलैंड, चिली, ब्राजील जैसे देशों से सेब आयात बढ़ रहा है। दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र होने से बिना शुल्क चुकाए अफगानिस्तान के रास्ते ईरानी सेब भारत पहुंच रहा है। ऐसे में कम लागत में ईरानी सेब के भारत पहुंचने से हिमाचली सेब नहीं टिक पा रहा है और अच्छे दाम नहीं मिल पाते। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो इससे हिमाचल की सेब अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो जाएगी और इस कारोबार से जुड़े लाखों लोग बर्बाद हो जाएँगे।

निगम भंडारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को वर्ष 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान विदेशी सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने और सभी प्रकार के कोल्ड ड्रिंक्स में 5 प्रतिशत सेब का कंस्ट्रेट मिलाने का वायदा किया था। लेकिन, केन्द्र सरकार ने इसके विपरीत विदेशी सेब पर आयात शुल्क घटाया है, जिससे हिमाचल के सेब की मांग कम हो रही है और बागवानों को नुक्सान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि एक ओर प्रधानमंत्री वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर पर इसे धरातल पर लागू नहीं किया जा रहा है, बल्कि उल्टे विदेशी सेब को प्रमोट कर हिमाचली सेब बाग़बानों की कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है। भंडारी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 5 लाख से अधिक बागवान सीधे तौर पर सेब बागवानी से जुड़े हुए हैं और प्रदेश में हर साल लगभग 4 करोड़ सेब की पेटियों के उत्पादन से 5 हजार करोड़ रुपए का कारोबार होता है। ऐसे में सेब के आयात शुल्क कम होना हिमाचल प्रदेश के इन पांच लाख परिवारों के हित में नहीं है।

मुसाफिर की घर वापसी का मामला केन्द्रीय आलाकमान के पास लंबित:किमटा

शिमला/शैल। प्रदेश कांग्रेस संगठन महामंत्री रजनीश किमटा ने कहा है कि पार्टी जल्द ही अपने सभी प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। उन्होंने कहा है कि भाजपा को इसकी कोई चिंता नही करनी चाहिए।

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए रजनीश किमटा ने कहा कि प्रदेश में अंतिम चरण में चुनाव होने है। उन्होंने कहा कि 7 मई से प्रदेश में नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने कहा इस दौरान कांग्रेस के स्टार प्रचारक प्रदेश के चुनाव प्रचार में उतरेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी ने प्रचार प्रसार का सारा खाका तैयार कर लिया है। उन्होंने कहा कि शिमला व मण्डी संसदीय क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी व विक्रमादित्य सिंह ने अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित सभी नेता, मंत्री भी प्रदेश के दौरे पर जाकर सभाओं को सम्बोधित करेंगे।

किमटा ने कहा कि पार्टी से निष्कासित नेताओ की घर वापसी का कोई भी फैंसला केंद्रीय आलाकमान ही करता है। उन्होंने कहा कि पच्छाद के पूर्व विधायक, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर के घर वापसी का मामला केंद्रीय आलाकमान के पास अभी भी लंबित पड़ा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुसाफिर ने पार्टी में शामिल होने के लिये बिना शर्त गुहार लगाई है, पर चूंकि यह पूरा मामला अनुशासन समिति की अनुशंसा से केंद्रीय आलाकमान के पास गया है और जल्द ही इस पर गुण दोष के आधार पर कोई निर्णय होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी उन्हें पार्टी में शामिल करने की अनुशंसा की है।

किमटा ने भाजपा नेताओं के उस आरोप पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी जिसमें वह प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा को अपनी नजर का चश्मा बदल लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा इस प्रकार के ब्यान देकर प्रदेश के शांत वातावरण को अशांत करने का असफल प्रयास कर रही है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह प्रदेश के शांत राजनीतिक माहौल को अशांत करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार भाजपा ने प्रदेश सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की है उससे भाजपा का असली चेहरा प्रदेश के लोगों के सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार को एक षडयंत्र के तहत गिराने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि भाजपा ऑपरेशन लोटस की जननी है पर प्रदेश में इसका यह ऑपरेशन पूरी तरह फेल हो गया। प्रदेश के लोग भाजपा को चारों खाने चित करेंगे। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में कांग्रेस चारों लोकसभा व छः विधानसभा उप चुनावों में शानदार जीत हासिल करेगी।

1500 रुपए पेंशन रुकवाने बार-बार चुनाव आयोग क्यों जा रही भाजपा:जैनब

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष जैनब चंदेल ने भाजपा पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा महिलाओं का सशक्तिकरण बर्दाश्त नहीं पा रही

है, इसलिए महिलाओं को 1500 रुपए पैन्शन प्रदान करने में अड़ंगे लगा रही है और बार-बार चुनाव आयोग के पास जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने अपने चुनावी गारंटी को पूरा करते हुए महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए पैन्शन प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि आरंभ की है। लेकिन पहले से जारी एक योजना को भाजपा नेता चुनाव आचार संहिता की आड़ में रुकवाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ महिला हितैषी होने का ढोंग रचती है, जबकि विपक्षी दल पूरी तरह से महिला शक्ति का विरोधी है। भाजपा चुनावों में वोट लेने के अलावा महिलाओं के लिए कुछ नहीं करती।

जैनब चंदेल ने कहा कि भाजपा 1500 रुपये पैन्शन रुकवाने का जितना मर्जी विरोध कर ले, लेकिन यह राशि अप्रैल 2024 से महिलाओं को मिलकर रहेगी। लाहौल व स्पीति जिला की लाभार्थी महिलाओं को 1500 रुपए पैन्शन दी जा रही है और प्रदेश के अन्य जिलों की महिलाओं को भी पहली अप्रैल 2024 से इस योजना का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक में योजना को पूरे प्रदेश में लागू करने के लिए 800 करोड़ रुपये का बजट भी मंजूर किया है तथा योजना को पहली अप्रैल से लागू करने की अधिसूचना तक जारी हो चुकी है। बावजूद इसके भाजपा बार-बार चुनाव आयोग पहुंचकर योजना पर रोक लगवाने की मांग कर रही है, जो उनके महिला विरोधी होने का स्पष्ट प्रमाण है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं की असलियत हिमाचल प्रदेश की महिलाओं के सामने आ चुकी है और महिला शक्ति चुनावों में भाजपा को कड़ा सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। जैनब चंदेल ने कहा कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना महिलाओं के जीवन मे बड़ा परिवर्तन लाएगी। उन्हें 18000 रुपये सालाना मिलेंगे, जिससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी और भाजपा को यह बात हज़म नहीं हो रही है।

कांग्रेस ने बाबा साहेब को प्रताड़ित, अपमानित किया, उन्हें राजनैतिक रूप से ख़त्म किया:अनुराग ठाकुर

शिमला/शैल। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस जाति, धर्म, क्षेत्र और भाषा के नाम पर वोट मांगती है वहीं भारतीय जनता पार्टी विकास, सेवा, सुशासन और

गरीब कल्याण के ऊपर वोट मांगती है। कांग्रेस की संस्कृति तोड़ने की है, जबकि हमारी संस्कृति जोड़ने की है। कांग्रेस ने ना सिर्फ़ बाबा साहेब को प्रताड़ित किया, अपमानित किया बल्कि उन्हें राजनैतिक रूप से ख़त्म करने का काम किया। अनुराग ठाकुर ने उपरोक्त बातें अपने हिमाचल प्रवास के दौरान कीं। अनुराग ठाकुर सर्वप्रथम देहरा विधानसभा के कांगड़ा में एससी सम्मेलन में सम्मिलित हुए और उसके पश्चात भोरंज विधानसभा के जाहु और घुमारवीं, बिलासपुर में स्थानीय कार्यक्रमों में जनसभाओं को संबोधित किया।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोग कांग्रेस की वादा खिलाफी से आक्रोशित हैं। जनता का गुस्सा उनके विधायकों के द्वारा पार्टी छोड़ने से सामने आ गया। अब जहां एक ओर 4 जून को देश में पूर्ण बहुमत की मोदी सरकार बनेगी वहीं हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा सरकार बनेगी और हमारा प्रदेश डबल इंजन की रफ्तार से विकास करेगा।

कांग्रेस द्वारा जातिगत जनगणना के वादे को लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने अपने 60 वर्षों के शासन में गरीबों और वंचितों के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति को सिर्फ छला है और ठगा है। देश के संविधान को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को कांग्रेस ने जीते जी अपमानित कर उन्हें राजनीति से बाहर कर दिया। वह तो भला हो कि गैर कांग्रेसी सरकार आई और वीपी सिंह जी की सरकार में बाबा साहब को भारत रत्न मिला। नरेंद्र मोदी जी ने आकर उनके पंच तीर्थ को विकसित किया, उनके जयंती को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित किया, संविधान दिवस मनाना शुरू किया।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों में वंचित हीं वरीयता में रहे हैं। अगर आप मोदी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को देखेंगे तो उनका अधिकतम लाभ गरीबों और वंचितों को हीं मिला है। उदाहरण स्वरूप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 71% लाभार्थी एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के 80% लाभार्थी छोटे और सीमांत किसान हैं जो एससी, एसटी और ओबीसी से आते हैं। 58% स्कॉलरशिप हमारे एसटी और एससी छात्रों को मिला है। मुद्रा योजना का 51% लाभ हमारे एससी और एसटी को मिला है। आवास योजना के अंतर्गत लगभग 54 से 55% लाभ हमारे एससी और एसटी भाइयों बहनों को मिला है। मोदी जी पीएम विश्वकर्म योजना लेकर आये जिसे सबसे बड़ा लाभ एससी-एसटी और ओबीसी समुदाय को मिल रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने भगवान वाल्मीकि जी के नाम पर अयोध्या का एयरपोर्ट बनाया। आज महान संत रविदास जी की भव्य प्रतिमा वाराणसी में बन रही है और भव्य धाम मध्य प्रदेश में बन रहा है।

भाजपा की चिंता छोड़े कांग्रेस:सत्ती

शिमला/शैल। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक सतपाल सत्ती ने कहा कि भाजपा को कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने

अनेकों बार सर्टिफिकेट आफ एक्सीलेंस दिया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी को किसी भी प्रकार की नसीहत देने की जरूरत नहीं है। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष के पुत्र ने भी अनेकों बार भारतीय जनता पार्टी को सर्टिफिकेट दिया है। विक्रमादित्य सिंह ने भी भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति की अनेकों बार प्रशंसा की है इसको भी कांग्रेस पार्टी को बार-बार सुनना चाहिए।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को कांग्रेस को ही संभालना चाहिए और अन्य किसी भी राजनीतिक दल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के छ: विधायक पार्टी को छोड़कर चले गए , यह कांग्रेस पार्टी की नालायकी के कारण है। अब केवल मात्र ब्यानबाजी कर कांग्रेस के नेता अपनी खींच मिटाने की प्रयास कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में अंतर्कलह चरम सीमा पर है, इसको कांग्रेस पार्टी मानने को तैयार ही नहीं है। अब हाल ही में गंगूराम मुसाफिर कांग्रेस में आना चाहते थे पर कांग्रेस पार्टी के राज्य प्रभारी ने चिटठी काट उनको रोक दिया, अब यह भी अंतर्कलह का एक भाग है। कांग्रेस पार्टी के राज्य सह प्रभारी तेजेन्द्र बिट्टू ने भी अपनी दुख भरी गाथा जनता के समक्ष रखी की किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में घुठन का माहौल है। कांग्रेस पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है जिसके अंदर कोई भी सवारी नहीं करना चाहता।

विक्रमादित्य जितनी भी उपलब्धियां गिना रहे है वह केंद्र द्वारा हिमाचल को दी गई है:गोविंद ठाकुर

शिमला/शैल। भाजपा के पूर्व मंत्री एवं संसदीय क्षेत्र प्रभारी गोविंद ठाकुर ने कहा की विक्रमादित्य सिंह जितनी भी उपलब्धियां गिना रहे है वह केंद्र द्वारा हिमाचल को दी गई है, उनका केवल मात्र इतना ही योगदान है कि उन्होंने डाकिए का काम किया है।

उन्होंने कहा की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को करोड़ों रुपए का फंड प्राप्त हुआ है। अगर इसका श्रेय विक्रमादित्य लेना चाहते हैं तो ले सकते है पर जनता सब जानती है कि पैसा कहां से आया है। अगर कांग्रेस के नेता फोरलेन की बात करें, टनल की बात करें सभी के लिए पैसा केंद्र सरकार द्वारा भेजा गया है। हाल ही में केन्द्रीय मंत्री और नितिन गडकरी ने हिमाचल प्रदेश के लिए एक लाख करोड़ का प्रावधान किया है जिससे सड़के बनेगी भी और उनको मरम्मत भी होगी।

उन्होंने कहा की नाबार्ड इस साल 2024-25 में हिमाचल प्रदेश को 34490 करोड़ रुपये देगा। यह 2023-24 के 31971.50 करोड़ से 8 प्रतिशत अधिक है। यह फैसला 31 जनवरी 2024 को आयोजित क्रेडिट सेमिनार में दी गई थी।

हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री पोषण स्कीम के तहत केंद्र की ओर से साढ़े 42 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया था। इसमें मंडी को सबसे ज्यादा करीब साढ़े छह करोड़ की राशि दी गई थी।

यह स्पष्ट है कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के साथ कभी भेदभाव नहीं किया और जितने भी आरोप कांग्रेस पार्टी के नेता लगा रहे हैं वो बे-बुनियाद है। आपदा के समय भी केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को 1800 करोड़ की राहत राशि भेजी थी और साथ ही 21000 घर निर्माण करने की स्वीकृति दी, क्या कांग्रेस के नेताओ को यह दिखता नहीं?

गोविंद ठाकुर ने कहा कि चीन की सीमा से सटे हिमाचल प्रदेश में स्पीति का गिउ गांव को पहली बार मोबाइल नेटवर्क से जुड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर ग्रामवासियों से फोन पर बात भी की। पीएम मोदी ने गांववासियों के साथ 13 मिनट से अधिक समय तक फोन पर बात की। यह है हमारा नेतृत्व, नीति और नियत जनता के साथ सीधा संवाद भी करते हैं और विकास भी देते हैं।

सुक्खू सरकार प्रदेश में चुनाव से पहले दंगा कराने जैसी स्थिति बनाना चाहती है:बिंदल

शिमला/शैल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिन्दल ने कहा कि सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की सरकार प्रदेश में चुनाव से पहले दंगा कराने जैसी स्थिति बनाना चाहती है। एक चुने हुए

विधायक को भरी सभा में कुटने, मारने, धमकी देने की बात कहते हुए प्रदेश में गुंडो को खुली छूट दे दी जिसका परिणाम हुआ पालमपुर में दिन दिहाड़े युवती के उपर धारदार हथियार से 12 बार वार करके उसे अधमरा कर दिया और एक की जान ले ली, यह मामला रूका नहीं है। मुख्यमंत्री के उपर हम आरोप लगाते हैं कि उनके उकसाने के बाद बद्दी की भयानक घटना हुई जहां सरेआम गोलियां चली। चम्बा की नृशंस हत्या के बाद से लेकर आज तक की सभी घटनाएं इस बात को साबित करती है कि गुंडो को सरकार का संरक्षण प्राप्त है और हिमाचल के अनेक स्थानों की जनता खौफ के साये में जी रही है। एक भी घटना पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री व मंत्रियों द्वारा खेद व्यक्त न करना, माफी न मांगना और भी चिंताजनक बात है।

सिरमौर में नुक्कड़ सभाओं में डॉ. बिन्दल ने कहा कि पिछले डेढ़ साल में जिला सिरमौर के समस्त विकास कार्य कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस सरकार ने बंद करा दिए हैं। 90 से ज्यादा संस्थान जिनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्कूल, कॉलेज, तहसील, उप तहसील, पटवार सर्कल व अन्य कार्यालय शामिल है और यह कार्यालय जनता को सेवाएं दे रहे थे, चले हुए थे, इन्हें बद करके सिरमौर की जनता के साथ सुखविन्द्र सरकार ने धोखा किया है। सिरमौर का एक मात्र मैडिकल कॉलेज जिसके लिए केन्द्र की भाजपा सरकार ने 265 करोड़ रूपये दिए उसका काम 16 महीने से बंद पड़ा है और उस मैडिकल कॉलेज के स्टाफ का षड़यंत्र के तहत कहीं बदलने का इरादा सरकार रखती है। मैडिकल कॉलेज का काम बंद होने से हजारों-हजारों मरीजो को भारी नुकसान हो रहा है। सिरमौर में पूर्व भाजपा सरकार में जो तेज गति से सड़कों और पुलों का जाल बिछ रहा था व सब कार्य स्टैण्ड स्टिल हो गए हैं केवल एक उद्योग सिरमौर में चल रहा है उसका काम है ट्रांसफर उद्योग। विरोधियों की प्रताड़ना करना, ट्रांसफर करना और भ्रष्टाचार करना यही काम पूरे सिरमौर में चला है।

डॉ. बिन्दल ने कहा कि सिरमौर की जनता डेढ़ साल से कांग्रेस के खिलाफ खड़ी हो गई है और नरेन्द्र भाई मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करेगी।

भाजपा कांग्रेस के जनविरोधी निर्णयों को लेकर जनता में जाएगी:रणधीर शर्मा

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुक्खु के ब्यान को विधायक रणधीर शर्मा ने हास्यास्पद बताया जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार के 15 महीने के कार्यकाल को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से प्रश्न करते हुए कहा कि ऐसी कौन सी उपलब्धि है जिसे लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं ? उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया है जिसे लेकर जनता के बीच जा रहे है ? उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि इन 15 महीनों में मात्र जनता को तंग किया, परेशान किया चुनावी वायदे व गारंटीया पूरे करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। महिलाओं को 1500 रूपये देने के वायदे पर सरकार बनाने वाली कांग्रेस डेढ़ साल बीत जाने के बाद भी वायदे को पूरा नहीं कर पाई है। जनता को भ्रमित कर रहे हैं कि मई से यह राशि महिलाओं को दी जाएगी परंतु ज़ब बजट में एक तक का प्रावधान नहीं किया गया तो कैसे इस गारंटी को पूरा किया जाएगा।

उन्होंने कहा कांग्रेस ने गारंटी दी थी कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे परंतु इसके बारे में भी सरकार कोई कदम नहीं उठा पायी है। कांग्रेस की यह भी गारंटी थी कि 100 रूपये किलो दूध और 2 रूपये किलो गोबर किसानों से खरीदा जाएगा परंतु वो भी एक जुमला ही साबित हुआ है। 5 लाख नौकरी का वायदा कर आज तक एक भी युवक को नौकरी इस सरकार ने नहीं दी है उल्टा आउटसोर्स पर लगे 10,000 युवाओं को नौकरी से निकाल दिया गया। इस सरकार ने 15 महीने में 1500 से ज्यादा संस्थान बंद करने का काम इस निक्कमी सरकार ने किया है। सरकार ने आते ही 6रूपये लीटर डीजल के रेट में बढ़ोतरी, 15 रूपये सीमेंट कि बोरी पर बढ़ौतरी कर जनता पर महंगाई का बोझ डाला क्या इसी को आधार बनाकर ये सरकार जनता से वोट मांगेगी। इस सरकार ने तो मंदिरों को भी नहीं बक्शा देवी दर्शन के लिए मंदिरो पर टैक्स लगाने की प्रथा मुख्यमंत्री ने शुरू की है, इतने जनविरोधी निर्णय लेकर जनता को त्रस्त करने का कार्य इस सरकार ने किया है।

उन्होंने कहा मुख्यमंत्री सुक्खु जनता को गुमराह करना बंद करें, जनता को ठगना बंद करें। भाजपा कांग्रेस सरकार के 15 महीने के जनविरोधी निर्णयों को लेकर जनता के बीच जाएगी। केंद्र सरकार की उपलब्धियां, जनहित व देशहित के कार्य, गरीबों के लिए कार्य, देश को दुनिया की पाँचवी अर्थव्यस्था बनाने के लिए कार्य, देश से आंतकवाद, भ्रष्टाचार को समाप्त करना, काशी विश्वनाथ में बाबा शिवधाम, अयोध्या में रामजन्म भूमि पर भव्य राममंदिर बनाने का कार्य इन सभी मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी। जनता प्रधानमंत्री मोदी के किए कार्य पर इस बार जनता भाजपा को वोट देगी। 4/4 की सीट जीत कर भाजपा तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्पित है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

डॉ.आस्था अग्निहोत्री ने भी हमीरपुर से लड़ने में दिखाई असमर्थता

हमीरपुर में प्रत्याशी का चयन बना सरकार और संगठन की परीक्षा
सरकार के दावे लगे दाव पर

शिमला/शैल। हमीरपुर लोकसभा सीट पर लम्बे अरसे से भाजपा का कब्जा चला आ रहा है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर वहां से भाजपा सांसद हैं। अनुराग ठाकुर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रखर और मुखर आलोचकों में गिने जाते हैं। इस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार

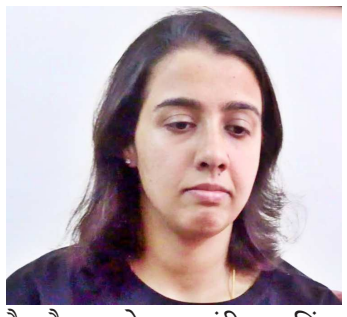

है और इसके मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमीरपुर के नादौन क्षेत्र से आते हैं। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ऊना के हरोली क्षेत्र से आते हैं। पिछले विधानसभा चुनावों में हमीरपुर से भाजपा एक भी सीट नहीं जीत पायी थी। लेकिन अब जो राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस में बगावत उभरी उसका केन्द्र भी हमीरपुर और ऊना जिले ही रहे हैं। दोनों जिलों में कांग्रेस के दो-दो विधायकों ने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करके बगावत को अंजाम दे दिया। हमीरपुर में तो निर्दलीय विधायक ने भी राज्यसभा में कांग्रेस के खिलाफ वोट कर दिया। इस क्रॉस वोटिंग के कारण राज्यसभा में मिली हार के बाद कांग्रेस के यह चारों विधायक दल-बदल कानून के तहत निष्कासित हो गये हैं। यह सब भाजपा में शामिल हो गये हैं भाजपा ने कांग्रेस के सभी बागियों को उपचुनाव में अपना उम्मीदवार भी नामजद कर दिया है।

लेकिन कांग्रेस में घटे इस विद्रोह के कारण पार्टी अभी तक लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों के लिये उम्मीदवारों का चयन नहीं कर पा रही है। लोकसभा के लिये उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना के पूर्व विधायक सतपाल रायजादा के नाम की घोषणा कर दी। यह दावा किया की रायजादा का नाम फाइनल हो गया है। परंतु इसी बीच मुकेश अग्निहोत्री की बेटी डॉ.आस्था अग्निहोत्री का नाम उम्मीदवार के रूप में चर्चा में आ गया। इस पर डॉ. आस्था अग्निहोत्री को एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से यह कहना पड़ा कि वह अभी मातृ शोक से उभर नहीं पायी है। इसलिए यह चुनाव लड़ने की मानसिकता में नहीं है। डॉ. आस्था का तर्क जायज है। लेकिन ऊना में मुकेश अग्निहोत्री के परिवार के बाहर कांग्रेस में उसी स्तर का कोई दूसरा नाम भी सामने नहीं है। लेकिन अग्निहोत्री पर भी यह सवाल उठने लग गया है कि उन्होने अपने चुनाव क्षेत्र हरोली के बाहर ऊना ही के दूसरे चुनाव क्षेत्रों में कोई बड़ा योगदान नहीं दिया है। इसलिये लोकसभा लड़ने में असमर्थता दिखाई जा रही है।

मुख्यमंत्री सुक्खू का चुनाव क्षेत्र नादौन भी हमीरपुर लोकसभा में ही आता है। एक समय मुख्यमंत्री की पत्नी कमलेश ठाकुर का नाम भी चर्चा में आया था। लेकिन बाद में चर्चा से गायब हो गया। भाजपा ने यहां से अनुराग ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है। अनुराग राहुल गांधी के सबसे बड़े आलोचकों में गिने जाते हैं। लेकिन हिमाचल कांग्रेस के किसी नेता या सुक्खू सरकार के किसी मंत्री ने आज तक अनुराग ठाकुर या मोदी सरकार की किसी योजना के खिलाफ कभी मुंह नहीं खोला है। इसलिये आज चुनाव में अनुराग के खिलाफ कांग्रेस का कोई बड़ा नाम आने को तैयार नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस हाईकमान भी शायद इस वस्तुस्थिति को समझ चुकी है। लेकिन हाईकमान हमीरपुर को लेकर फैसला लेने में शायद प्रदेश के नेतृत्व पर ज्यादा निर्भरता नहीं रखेगा। माना जा रहा है कि शायद हाईकमान मुख्यमंत्री या उपमुख्यमंत्री में से किसी एक के परिवार पर उपचुनाव लड़ने की जिम्मेदारी डाल दे। क्योंकि ऐसा करने से ही राज्य सरकार के दावों की सही परीक्षा हो पायेगी। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री दोनों के जिलों में इतनी बड़ी बगावत विधायक दल में हो गयी जिसका समय से पहले पता ही क्यों नहीं चल सका? यह सवाल अब तक अनुत्तरित है। इसके लिये विपक्ष को कोसने के अतिरिक्त कांग्रेस और कुछ नहीं कर पा रही है और यही कांग्रेस का सबसे बड़ा नकारात्मक पक्ष सिद्ध हो रहा है। आज कांग्रेस के पास छः विधायकों के पाला बदलने के अतिरिक्त और कोई मुद्दा ही केन्द्र के खिलाफ नहीं है।

क्या बाली का पत्र परोक्ष में

.....पृष्ठ 1 का शेष

का लक्ष्य रखा है। क्षेत्र के लोगों ने उन्हें भारी मतों से विजयी बनाकर विधायक बनाया है। इसलिये उनकी पहली प्राथमिकता विधानसभा चुनाव क्षेत्र है। उन्हें कोई और जिम्मेदारी सौंपने के लिये क्षेत्र के लोगों की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। बाली के पत्र से स्पष्ट हो जाता है कि वह अपने तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है। एक विधायक के नाते बाली का यह पत्र लिखना एकदम जायज है।

बाली मानते हैं कि प्रदेश में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। सुक्खू सरकार ने पांच लाख को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। बाली ने भी पांच हजार को अपने चुनाव क्षेत्र में रोजगार देने का वायदा किया है। बाली इस समय कैबिनेट रैंक में पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी संभाले हुये हैं। मुख्यमंत्री के विश्वस्तों में गिने जाते हैं। लेकिन बाली यह नहीं बता पाये हैं कि सरकार के पन्द्रह माह के कार्यकाल में वह और सरकार कितना रोजगार दे पाये हैं। जिस बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर स्व. जी.एस.बाली और फिर आर.एस.बाली ने भी रोजगार यात्राएं निकाली तो उसी मुद्दे पर सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा का चिन्ता उठाना और मुख्यमंत्री से सवाल पूछना कैसे गलत हो सकता है। रोजगार को लेकर विधानसभा सूत्रों में जितने भी विधायकों द्वारा सवाल पूछे गये हैं उनके जो भी जवाब दिये गये हैं उससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रदेश की जनता के सामने सच्चाई नहीं रखी जा रही है। शैल विधानसभा में आये प्रश्नों और उनके उत्तरों को पहले ही पाठकों के सामने रख चुका है।

बाली कांगड़ा से लोकसभा के उम्मीदवार बनते हैं या नहीं यह तो आने वाला समय ही बतायेगा। लेकिन बाली द्वारा रोजगार के मुद्दे का जिक्र करना और अपने विधान सभा क्षेत्र को प्राथमिकता देना कांग्रेस के बागियों के मुद्दे को समर्थन देना बन जाता है। बाली के पत्र से यह स्पष्ट झलकता है कि वह लोकसभा लड़ने के लिये तैयार नहीं है। क्योंकि सरकार की कथित उपलब्धियां भाषणों में तो गिनाई जा सकती हैं परन्तु व्यवहार में नहीं।

यह है पत्र

R. S. Bali
Secretary
All India Congress Committee

INDIAN NATIONAL CONGRESS

24, Akbar Road
New Delhi-110011
T: 011-23019080

16.04.2024

आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी,
राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी

आदरणीय सर,

मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है की आगामी संसदीय चुनावो में कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से मेरा नाम सर्वे में आया है और केंद्रीय चुनाव समिति में भी इसकी चर्चा हुई है। इसी के चलते मैं इस पत्र के माध्यम से अपने दिल की कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। मेरे पूजनीय पिता विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी के लिए ताउम आदरणीय मैडम सोनिया गांधी जी उनकी नेता रही है। मैडम ने भी हमेशा से एक बड़ी बहन व नेता की तरह मेरे पिताजी को राजनितिक रूप से मज़बूत करने के लिए हर संभव सहयोग दिया। मैं और मेरा परिवार इस के लिए उनका दिल की गहराइयों से सम्मान करता है।

आजतक, हमारे परिवार का अगर दिल्ली में कोई राजनीतिक रिश्ता रहा, तो वह केवल गांधी परिवार से रहा। मैंने कभी भी चुनावी राजनीति में आग लेने के बारे में नहीं सोचा, मैंने मात्र एक कार्यकर्ता बन कर कार्य किया। किसी भी पद या टिकट के लिए कभी भी लालसा मन में नहीं रखी व आवेदन भी नहीं किया. राजनीति का मतलब मेरे लिए संगठन और सेवा ही रहे। पिताजी का राजनीती में सहयोग करना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य रहा.

महोदय जी, मैंने अपने जीवन के 26 वर्ष कांग्रेस संगठन सेवा को समर्पित किये हैं। मैंने एनएसयूआई में वर्ष 1998 में बतौर कार्यकर्ता कार्य शुरू किया, वर्ष 2004 में हमारे नेता व प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जो उस समय युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके द्वारा मुझे युवा कांग्रेस का प्रदेश महासचिव बनाया गया. इसके उपरांत, 2012 में हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी द्वारा शुरू किये गए युवा कांग्रेस के प्रदेश के पहले चुनाव में मैंने भाग लिया और प्रदेश में जीत हासिल की।

युवा कांग्रेस में मेरे कार्य को देखते हुए स्वर्गीय श्री राजीव सातव जी के द्वारा मुझे पूरे देश की युवा कांग्रेस में सर्वश्रेष्ठ-प्रफॉर्मर चयनित कर मेरे काम को युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सराहा गया. उसके बाद मुझे पीसीसी में शामिल कर पहले प्रदेश सचिव और कुछ वर्षों बाद प्रदेश महासचिव और अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी का सदस्य बनाया गया। मेरे संगठन में लम्बे समय तक कार्य को देखते हुए, वर्ष 2021 में मुझे आदरणीय श्रीमती सोनिया गाँधी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी का राष्ट्रीय सचिव बनाया।

कोविड के अत्यावह दौर में पश्चिम बंगाल में विद्यानसभा के चुनाव घोषित हुए और उसी समय 27 फ़रवरी 2021 को मुझे पश्चिम बंगाल का सहप्रभारी नियुक्त किया गया. जिसका निर्वहन करते हुए मैंने सभी विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी का कार्य किया। भारत जोड़ो यात्रा में भी श्री राहुल गांधी जी के साथ विभिन्न राज्यों में कार्य किया। जिसकी सराहना आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने भी स्वयं पत्र के माध्यम से की।

श्री जीएस बाली जी के लिए लोगो की सेवा करना ही जीवन का लक्ष्य था और हमारे लिए उनकी खुशी सबसे अहम थी। अपने जीवन में जन सेवा में वह इतने वयस्त रहे की उन्होंने अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल नहीं रखा। स्वास्थ्य बिगड़ने के चलते उनका मात्र 67 वर्ष की उम्र में स्वर्गवास हो गया। यह मेरे परिवार को स्तब्ध कर देने वाला समय था।पिता जी के देहांत को अभी एक वर्ष भी नही हुआ था कि मेरी माता जी भी पिछले वर्ष 2023 में हमे छोड़ कर चली गई। एक वर्ष से भी कम अंतराल में हमने अपने घर के दौनो मुख्य स्तम्भ खो दिए। इस निराशा के दौर में मेरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने मुझे व परिवार को माता पिता व भाई-बहन की तरह सहारा दिया, साथ ही मेरे प्रदेश के लाखो लोगो ने परिवार बनकर हमें संभाला व हौसला दिया, जिसके लिए मैं और मेरा परिवार ताउम उनका ऋणी रहेगा।

महोदय जी, श्री जी एस बाली जी ने वर्ष 2012 में प्रदेश में रोजगार संघर्ष यात्रा की थी जिसे हमारे प्रदेश की जनता का भरपूर प्यार व सहयोग मिला था और उसके बाद 2012 मे प्रदेश में कांग्रेस की वापसी हुई थी. उनके इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैंने हमारी राष्ट्रीय नेता आदरणीय श्रीमती प्रियंका गाँधी जी व प्रदेश प्रभारी आदरणीय श्री राजीव शुक्ला जी से मिलकर प्रदेश में रोजगार संघर्ष यात्रा शुरू करने का आग्रह किया। मेरे आग्रह को श्रीमती प्रियंका जी ने आशीर्वाद दिया व इसके उपरान्त मुझे इस यात्रा की कमान सौंपते हुए इसका प्रदेश संजोयक नियुक्त किया गया।

नगरोटा बगवां में आयोजित विशाल रैली में प्रदेश प्रभारी आदणीय श्री राजीव शुक्ला जी की अध्यक्षता में, वर्तमान मुख्यमंत्री आदणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खु जी, वर्तमान उपमुख्यमंत्री आदणीय श्री मुकेश अग्निहोत्री जी सहित सभी विधायक, पीसीसी पदाधिकारी, वरिष्ठ नेताओं व हाई कमान के बहुत से शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर मेरे हाथ में मशाल सौंपी गई. श्री राजीव शुक्ला जी ने इसे मौके पर, प्रदेश में युवाओं को 5 लाख रोजगार व 680 करोड़ स्टार्टअप योजना के लिए देने का वादा किया। करीब 2 महीने तक सैकड़ों किलोमीटर चली इस यात्रा में प्रदेश के लाखो लोग जुड़े व जिस-जिस क्षेत्र से यह यात्रा निकली उस एरिया में पार्टी को जीत मिली। प्रदेश में सरकार को सत्ता में लाने में इस यात्रा की भी अहम भूमिका रही. इस यात्रा का समापन आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी के लिए नगरोटा बगवां में आयोजित मेरी विशाल चुनावी रैली से हुआ। मैं पार्टी का शुक्रगुज़ार हूँ की रोज़गार के लिए किये गए इन वादों को कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल किया गया.

विधानसभा चुनावों में मेरे विधानसभा परिवार ने मुझ पर विश्वास जताते हुए प्रदेश में सबसे अधिक वोट देकर मुझे विजयी बनाया। मैंने अपने चुनावो के दौरान विधानसभा का कोई घोषणा पत्र जारी नहीं किया केवल "जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं" के सिद्धांत पर रहा।

अपने इलेक्शन के दौरान, मैंने अपनी विधानसभा में 5 हजार रोजगार देने व श्री जीएस बाली जी के समय जो विकास की गंगा बही थी, उसे जारी रखने का संकल्प दोहराया।

हमारे नेता आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खु जी ने मुझे पर्यटन विभाग के चेयरमैन की ज़िम्मेदारी सौंपी।अपने विभाग में मैंने रात-दिन एक कर के प्रदेश में पर्यटन को विकसित करने के लिए कई अहम योजनाएं स्वीकृत कराई है. मेरी एक साल की वो मेहनत अब ज़मीन पर उतरने वाली है, जिसके महत्व को लोग अब समझ पाएंगे और इसको लाभ प्रदेश की जनता को अब मिलेगा। अपने नगरोटा विधानसभा में भी मुख्यमंत्री जी द्वारा मैंने विभिन्न विभागो के शिलान्यास करवाए व उनसे कई अहम घोषणाएं करवाई. उन कार्यों को भी आगे बढ़ाना ज़रूरी है।पहली बार विधायक बनकर, मात्र एक वर्ष में ही अगर पार्टी मुझे चुनाव लड़ाती है तो मैंने जो अपने नगरोटा बगवां परिवार से वादे किये हैं, उन्हें पूरा करना भी ज़रूरी है. इस सबका भी पहले हमें कोई समाधान निकालना पड़ेगा।

सबसे अहम बात ये है की मेरे लोक सभा चुनाव लड़ने के सम्बन्ध मे किसी ने भी अभी तक मुझसे कोई बात नहीं की है. मेरी प्राथमिकता विकास एवं रोज़गार है, जो हमारा संकल्प भी है. यह मेरे लिए बहुत संवेदनशील विषय है व पार्टी सहित मेरी विश्वसनीयता से जुड़ा है. मैंने हमेशा पार्टी के हर निर्णय को सम्मान दिया है. इसलिए मैंने पत्र के माध्यम से ये बात आपके ध्यान में लाने का फैसला लिया है. मेरा निवेदन है की आप कोई भी निर्णय लेने से पहले मुझसे बात ज़रूर करेंगे ताकि मैं इस सम्बन्ध में अपने विधानसभा परिवार के साथ बैठ कर निर्णय ले सकू.

आभार सहित

RS Bali

आर एस बाली